भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता : वैष्णव

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आठ गुना बढ़कर 3 लाख करोड़

'मेक इन इंडिया' से 300+ मोबाइल विनिर्माण इकाइयां

नई दिल्ली, 10 अगस्त. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को घोषणा की कि भारत ने स्मार्टफोन के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनने का गौरव हासिल किया है. बेंगलुरु में मेट्रो परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान उन्होंने बताया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का मूल्य अब 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले 11 वर्षों में छह गुना वृद्धि दर्शाता है.

वैष्णव ने आगे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में आठ गुना वृद्धि हुई है और यह अब 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस उपलब्धि के साथ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है.

मेक इन इंडिया की सफलता- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 में भारत में केवल दो मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थीं, जो अब बढ़कर 300 से अधिक हो गई हैं. 2014-15 में भारत में बिकने वाले मोबाइल फोनों में से केवल 26त्न का निर्माण देश में होता था, जबकि अब यह आंकड़ा 99.2त्न तक पहुंच गया है.

मोबाइल फोन विनिर्माण का मूल्य वित्त वर्ष 2014 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4,22,000 करोड़ रुपये हो गया है. वैष्णव ने इस वृद्धि को सरकार की उस दूरदर्शिता का परिणाम बताया, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी उत्पादन का केंद्र बनाना और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना है.

देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 144 पहुँची

भारतीय रेलवे लगातार अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश में सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 144 हो गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि सरकार का मुख्य ध्यान देश के रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर है .वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इन ट्रेनों में तेज एक्सीलरेशन, कवच सिस्टम, पूरी तरह से सीलबंद गैंगवे, ऑटोमेटिक दरवाजे और आरामदायक सीटें जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं. यात्रियों की सुविधाओं के लिए मिनी पैंट्री, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर, रिक्लाइनिंग सीटें और हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट जैसी व्यवस्थाएँ भी की गई हैं. सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय भी इन ट्रेनों का हिस्सा हैं.

रुपये में 42 पैसे की साप्ताहिक गिरावट

मुंबई, 10 अगस्त (वार्ता) विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में मजबूती से बीते सप्ताह रुपया 42.50 पैसे (0.49 प्रतिशत) लुढ़ककर 87.61 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया.

रुपये के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहा. पहले दो दिन इसमें बड़ी गिरावट रही और मंगलवार को यह 87.88 रुपये प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बुधवार और गुरुवार को मजबूत होने के बाद शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ 87.61 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. इससे पहले के सप्ताह में भी रुपया 62 पैसे टूटा था.

विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय पूँजी बाजार में बिकवाली से भारतीय मुद्रा दबाव में रही.

देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए तत्काल भूमि सुधार

भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य

केंद्र-राज्य समन्वय हेतु जीएसटी जैसी परिषद

नई दिल्ली, 10 अगस्त. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने रविवार को कहा कि देश को 2047 तक एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और निवेश केंद्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्काल और बड़े भूमि सुधारों की आवश्यकता है.

सीआईआई के बयान के अनुसार, भारत ने कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है, लेकिन भूमि क्षेत्र में अभी भी चुनौतियाँ मौजूद हैं, जो औद्योगिक विकास को धीमा कर रही हैं और निवेशकों को हतोत्साहित कर रही हैं. सीआईआई ने कहा कि भारत का मजबूत नीतिगत ढांचा, औद्योगिक क्षमताएं, विशाल घरेलू बाजार और युवा कार्यबल इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं. इन अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए, भारत को एक दूरदर्शी प्रतिस्पर्धात्मकता एजेंडे की आवश्यकता है, जिसमें भूमि सुधार एक प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए.

समन्वय और डिजिटली करण पर जोर- सीआईआई ने केंद्र और राज्यों के बीच भूमि नीति के समन्वय के लिए जीएसटी जैसी एक परिषद बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि भूमि प्रशासन मुख्य रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है. इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि वर्तमान में देश में औद्योगिक भूमि बैंक मुख्यत: एक सूचना उपकरण है, जिसे एक नेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में अपग्रेड किया जाना चाहिए. यह प्लेटफॉर्म न केवल डेटा प्रदान करे, बल्कि एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से भूमि का सीधा आवंटन भी करे.

मौजूदा सिस्टम की खामियों पर प्रकाश डालते हुए सीआईआई ने कहा कि भारत में संपत्ति के पंजीकरण में नौ प्रक्रियाएं शामिल हैं और 58 दिन लगते हैं, साथ ही संपत्ति के मूल्य की लगभग 8 प्रतिशत राशि भी खर्च होती है.

ग्रामीण विकास और निवेश को बढ़ावा

सीआईआई ने राज्यों से भूमि विवादों पर आंकड़े प्रकाशित करने, मिश्रित उपयोग विकास को प्रोत्साहित करने वाले लचीले ज़ोनिंग नियमों को अपनाने, पर्यावरणीय स्थिरता को औद्योगिक नियोजन में एकीकृत करने और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बड़े ग्रामीण भूमि खंडों को औद्योगिक गलियारों से जोड़ने का आग्रह किया. सीआईआई के अनुसार, ये सुधार न केवल भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, बल्कि ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देंगे, अधिक निवेश आकर्षित करेंगे और समावेशी आर्थिक विकास को गति देंगे.

भारत ने पाँच प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 10 अगस्त. पिछले पाँच वर्षों में भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों का विस्तार करते हुए पाँच प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी.

मंत्री ने बताया कि इस अवधि में भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (2021), भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (2022), भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (2022) और भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (2024) जैसे समझौते लागू हुए हैं, जबकि भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (2025) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और उसका कार्यान्वयन लंबित है.

व्यापार समझौतों के परिणाम- मंत्री के व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते में 2023-24 में निर्यात में 14 प्रतिशत और 2024-25 में 8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, हालांकि व्यापार संतुलन नकारात्मक रहा. मॉरीशस के साथ लगातार व्यापार अधिशेष बना रहा, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए समझौते में निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि हुई, जिससे घाटा बढ़ गया.

एफआईआई ने अगस्त में बाजार से निकाले 13,699 रुपये

मुंबई, 10 अगस्त (वार्ता) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने अगस्त में भारतीय पूंजी बाजार से 13,699 करोड़ रुपये (156.4 करोड़ डॉलर) की शुद्ध निकासी की.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एफआईआई ने अगस्त में शुद्ध रूप से 204.6 करोड़ डॉलर की इक्विटी बेची. हालांकि उन्होंने डेट में 31 करोड़ डॉलर और म्यूयुअल फंड में 18.8 करोड़ डॉलर लगाये. हाइब्रिड इनस्ट्रूमेंट में उन्होंने 1.6 करोड़ डॉलर की शुद्ध निकासी की. इस प्रकार उन्होंने शुद्ध रूप से 156.4 करोड़ डॉलर निकाले. एफआईआई पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं.

इंडस्ट्रियल सॉल्ट की पहली रेक रवाना

अहमदाबाद मंडल का नया रिकॉर्ड, पहली रेक का लदान और राजस्व

अहमदाबाद ,10 अगस्त. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने 9 अगस्त 2025 को गांधीधाम क्षेत्र के सनोसरा गुड्स शेड से वडोदरा मंडल के दहेज के लिए इंडस्ट्रियल सॉल्ट की पहली रेक रवाना कर नया कीर्तिमान बनाया.

इस रेक में 58 BOXNH रु वैगनों में कुल 3,851.2 टन इंडस्ट्रियल सॉल्ट लोड किया गया, जिससे रेलवे को ?31.69 लाख का मालभाड़ा मिला. माल चौगुले सॉल्ट वर्क्स (प्रा.) लिमिटेड का था और रेक ने 673.57 किमी दूरी तय की.

अहमदाबाद मंडल पश्चिम रेलवे का प्रमुख माल लदान केंद्र है, जो कुल माल ढुलाई का लगभग 40त्न योगदान देता है. इसमें मुंद्रा, कांडला और टुना टेकरा जैसे बड़े बंदरगाह शामिल हैं. मंडल में 76 माल ढुलाई केंद्र, 7 गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल, 6 निजी माल टर्मिनल, 16 निजी साइडिंग और 37 गुड्स शेड हैं. पिछले वर्ष यहां से 46.77 मिलियन टन माल लादा गया था.

भविष्य की योजनाएं और विकास

रेलवे की सक्रिय विपणन नीति से ग्राहकों को भरोसेमंद सेवा मिली और नए कारोबार के अवसर बने. आने वाले 2-3 वर्षों में मंडल में 6 नए जीसीटी बनाए जाएंगे. नलिया-वायोर नई रेल लाइन से अल्ट्राटेक सीमेंट और अडानी सीमेंट को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे 1.2 करोड़ टन की उत्पादन क्षमता बढ़कर 1.8 करोड़ टन हो सकती है. यह पहल न केवल आर्थिक मजबूती लाएगी बल्कि पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा देगी.

गेहूँ-तेल महंगे, चावल सस्ता हुआ

दालों में मिला-जुला रुख बरकरार

आटा 16 रुपये महंगा चावल सस्ता

नई दिल्ली, 10 अगस्त (वार्ता). बीते सप्ताह घरेलू थोक जिंस बाजारों में गेहूँ, गुड़ और चीनी के भावों में तेजी देखी गई. वहीं, खाद्य तेल भी महंगे हुए, जबकि दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा. चावल के औसत भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई.

सप्ताह के दौरान गेहूँ का औसत भाव 10 रुपये बढ़कर 2,849.23 रुपये प्रति क्विंटल हो गया. आटे की कीमत में भी 16 रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 3,317.21 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुँच गया. इसके विपरीत, चावल की औसत कीमत तीन रुपये घटकर 3,802.20 रुपये प्रति क्विंटल रही. गुड़ और चीनी के दाम भी बढ़े, जहाँ गुड़ 58 रुपये और चीनी 48 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

खाद्य तेल- सभी प्रमुख खाद्य तेलों के दाम में साप्ताहिक तेजी देखी गई. सरसों तेल में औसतन 168 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा, मूँगफली तेल 60 रुपये, वनस्पति 20 रुपये, सोया तेल 57 रुपये, सूरजमुखी तेल 20 रुपये और पाम ऑयल 42 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ.

दालों का हाल

दालों के बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला. चना दाल 42 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई, जबकि मसूर दाल 42 रुपये फिसल गई. तुअर दाल में दो रुपये की मामूली गिरावट आई. वहीं, उड़द दाल में करीब 12 रुपये और मूंग दाल में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त रही.

ईवी की रफ्तार बढ़ाने को चार्जिंग नेटवर्क जरूरी : मारुति सुजुकी

नई दिल्ली, 10 अगस्त.मारुति सुजुकी इंडिया के एक अधिकारी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की स्वीकार्यता बढ़ाने में सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है.वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पार्थो बनर्जी ने बताया कि ग्राहकों की रेंज एंजाइटी के कारण ईवी को घरेलू इस्तेमाल के लिए स्वीकार करने में बाधा आ रही है.बनर्जी ने कहा कि भले ही इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री दोगुनी हुई है, लेकिन यह संख्या अभी भी बहुत कम है.

ट्रंप टैरिफ से मिशिगन ऑटो उद्योग बेहाल

व्हिटमर ने ओवल ऑफिस में जताई चिंता, नौकरियां और मुनाफा दोनों खतरे में

वाशिंगटन, 10 अगस्त- मिशिगन की गवर्नर ग्रेटा व्हिटमर ने इस सप्ताह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निजी तौर पर मुलाकात कर उन्हें बताया कि उनके लगाए गए टैरिफ राज्य के ऑटोमोटिव उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे नौकरियां और मुनाफा खतरे में है.

डेमोक्रेट नेता व्हिटमर ने मंगलवार को ओवल ऑफिस में हुई बैठक में एक स्लाइड प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रंप के आयात शुल्क कैसे एक ऐसे राज्य में

गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसने उन्हें 2024 में चुनाव जीतने में मदद की थी. यह ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद व्हिटमर की तीसरी व्हाइट हाउस यात्रा थी, लेकिन पिछली यात्राओं के विपरीत यह बैठक बंद दरवाजों के पीछे हुई.सूत्रों के अनुसार, व्हिटमर ने बर्फ़ीले तूफान के बाद संघीय सहायता की आवश्यकता और मेडिकेड में बदलाव में देरी का भी अनुरोध किया. हालांकि, ट्रंप ने कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता नहीं दी.

ट्रंप के व्यापार उपायों के तहत, अमेरिकी वाहन निर्माताओं को स्टील और एल्युमीनियम पर 50%, चीन से आने वाले पुर्जों पर 30%, और 2020 के व्यापार समझौते में शामिल न होने वाले कनाडा और मैक्सिको के सामान पर 25%, तक का टैरिफ देना पड़ रहा है.

समाचार विशेष

राजनीतिक उलटफेरों की जमीन नौतन विधानसभा सीट

पटना. बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का नौतन विधानसभा क्षेत्र राज्य की उन खास सीटों में शामिल है, जहां राजनीति और पौराणिकता दोनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है. जातीय और सियासी, दोनों लिहाज से भी यह सीट बेहद जटिल मानी जाती है.

पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित नौतन विधानसभा क्षेत्र फिलहाल एक बार फिर चुनावी रंग में रंगने को तैयार है. यहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नारायण प्रसाद विधायक हैं, जो पर्यटन मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की, हालांकि 2009 के उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बावजूद वे इस सीट पर भाजपा के सबसे मजबूत चेहरों में गिने जाते हैं.

जनगणना और मतदाताओं की बात करें तो 2024 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार नौतन की कुल जनसंख्या 4,77,900 है, जिसमें 2,55,286 पुरुष और 2,22,614 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1 जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या 2,86,873 है, जिनमें 1,54,334 पुरुष और 1,32,520 महिलाएं हैं. नौतन कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था. 1951 से लेकर 1985 तक कांग्रेस ने इस सीट पर लगातार कब्जा बनाए रखा. केदार पांडे, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, 1967 से 1977 तक चार चुनाव जीते. इसके बाद उनकी पत्नी कमला पांडे ने 1980 और 1985 में जीत दर्ज की. हालांकि, 1990 के बाद से कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ी और उसके बाद पार्टी इस सीट पर लगातार पिछड़ती चली गई. 1990 के दशक के बाद नौतन में जनता दल (यूनाइटेड) और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी समता पार्टी का दबदबा बढ़ा.

भाजपा की दो बार जीत

वहीं, भाजपा ने इस सीट पर दो बार जीत हासिल की है. नारायण प्रसाद 2015 और 2020 में विधायक बने और फिलहाल इस सीट पर भाजपा की पकड़ मजबूत मानी जा रही है. इसके अलावा, भाकपा, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां से एक-एक बार विजयी रह चुके हैं. मुस्लिम और यादव समुदाय की ज्यादा आबादी के बावजूद, यह क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए अब तक अभेद्य बना हुआ है. यही कारण है कि यह सीट राज्य की सियासत में खास महत्व रखती है, जहां जातीय आधार पर वोटिंग पैटर्न स्पष्ट नहीं है और हर चुनाव में समीकरण बदलते दिखते हैं.

अल्पसंख्यक कार्ड पर कांग्रेस-सपा एक सुर में ...

उमर अंसारी को बनाया मुद्दा, क्या चलेगा मुस्लिम दांव?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है, और मिशन-2027 को लेकर सियासी पारे में लगातार उबाल देखा जा रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने रणनीतिक मोर्चेबंदी शुरू कर दी है. पार्टी एक ओर जहां संगठन सृजन महाअभियान के जरिए बूथ स्तर तक अपने ढांचे को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं मुस्लिम वोटबैंक को साधने के लिए भी खुलकर दांव चला जा रहा है.

उमर अंसारी की गिरफ्तारी के बहाने कांग्रेस ने यूपी सरकार पर सीधा हमला बोला है. अब इसी मुद्दे को विपक्ष, खासकर सपा और कांग्रेस, मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचने के बड़े मौके के रूप में देख रहा है.

विपक्ष ने खेला मुस्लिम वोटबैंक का दांव

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा-2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है. पार्टी जहां एक ओर संगठन सृजन महाअभियान के जरिए हर बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी ओर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश में मुस्लिम वोटबैंक पर भी खास नजर है. इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी का न सिर्फ खुलकर विरोध किया है, बल्कि इसे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्दा बनाकर योगी सरकार पर हमला बोला है.

उमर अंसारी की गिरफ्तारी को बनाया मुद्दा

पूर्वांचल की राजनीति में कभी मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का खासा असर रहा है. ऐसे में कांग्रेस ने अब उनके बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर सियासी निशाना साधा है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि यूपी कांग्रेस के संगठन महामंत्री अनिल यादव ने सीधे तौर पर योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी करार देते हुए दावा किया कि प्रदेश में मुस्लिमों, दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है. उनका कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रही है.

ममता की पार्टी के वरिष्ठ किनारे हो रहे हैं

कोलकाता. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में संक्रमण का समय चल रहा है. कांग्रेस छोड़ कर उनके साथ आए तमाम पुराने नेता एक एक करके रिटायर हो रहे हैं या किनारे किए जा रहे हैं.

ममता के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में नए नेता कमान संभाल रहे हैं. अभिषेक को लोकसभा में पार्टी का नेता बना दिया गया है. वे लोकसभा में भाजपा, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के बाद चौथी सबसे बड़ी पार्टी के नेता बन गए हैं. अभी तक सुदीप बंदोपाध्याय यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे. सेहत के हवाले उनको पद से हटा दिया गया है. अभिषेक के लोकसभा में नेता बनने के बाद दूसरा बड़ा बदलाव मुख्य सचेतक का हुआ. तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी थे. उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह काकोली घोष दस्तीदार को मुख्य सचेतक बनाया गया है.

विशेष | **तेज प्रताप के तेवर से बिहार की राजनीति में आया नया मोड़**

क्या बड़े भैया बिगाड़ेंगे छोटे का खेल?

पटना. बिहार चुनाव से पहले एक और नया मोर्चा तैयार हो गया है. टीम तेज प्रताप ने पांच दलों के साथ गठबंधन किया है. इसमें प्रदीप निषाद की विकास वंचित इंसान पार्टी (वीवीआईपी), भोजपुरिया जन मोर्चा (बीजेएम), प्रगतिशील जनता पार्टी (पीजेपी), वाजिब अधिकार पार्टी (डब्ल्यूएपी) और संयुक्त किसान विकास पार्टी (एसकेवीपी) शामिल है. इस गठबंधन की घोषणा खुद तेज प्रताप यादव की है.

बिहार में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी और परिवार से बेदखल होने के बाद अपनी एक अलग 'टीम तेज प्रताप' तैयार कर ली है. टीम तेज प्रताप ने बिहार में कुछ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर लिया है. खुद तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने और राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है.

बिहार की राजनीति में एक नया मोड़- तेज प्रताप के इस फैसले से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है. मई महीने में अनुष्का प्रकरण में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया था. इसके बाद तेज प्रताप यादव ने 'टीम तेज प्रताप' के नाम से दल बनाया और चुनाव की तैयारी शुरू की. अब वीवीआईपी नाम की पार्टी के साथ ही कुछ अन्य छोटी पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर लिया है.

इस वोट बैंक पर 'टीम तेज प्रताप' का फोकस- वीवीआईपी प्रदीप निषाद की पार्टी है. कभी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के सहयोगी रहे प्रदीप निषाद ने जून में वीवीआईपी (विकास वंचित इंसान पार्टी) का गठन किया था. इसका चुनाव चिन्ह नाव छाप है, जो पहले मुकेश सहनी की पार्टी का था. तेज प्रताप यादव की पार्टी 'टीम तेज प्रताप' के साथ इसका गठबंधन हो गया है. 'टीम तेज प्रताप' यादव और मुस्लिम वोटर व वीवीआईपी निषाद समाज के वोटर को टारगेट करेंगे. ये दोनों वर्ग के वोटर बिहार में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

आरजेडी के लिए मुसीबत

अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन यादव, मुस्लिम और निषाद समाज को किस हद तक अपने पाले में करने में कामयाब होगा. फिलहाल, तेज प्रताप के तेवरों ने आरजेडी की टेंशन तो बढ़ा रखी है. इसकी मुख्य वजह ये है कि यादव और मुस्लिम उसका कोर वोट बैंक रहा है. ऐसे में परिवार से बेदखल किए गए तेज प्रताप द्वारा अपनी पार्टी बनाना और फिर छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन करना, आरजेडी के लिए मुसीबत बना हुआ है.